ईरान के नये राष्ट्रपति के अधीन अपेक्षित आगामी परिवर्तन और भारत के लिए इसके मायने

चर्चा में क्यों ?

- ईरानियों ने सुधारवादी मसूद पेजेशकियन को इस्लामिक गणराज्य के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना है , जो इब्राहिम रईसी की जगह लेंगे, जिनकी मई में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

राष्ट्रपति चुनाव की पृष्ठभूमि

- ईरान में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव 19 मई को पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मौत की पृष्ठभूमि में हुए।
- 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा, जिसमें केवल 39.92 प्रतिशत पात्र मतदाताओं ने भाग लिया।
- ईरानी सरकार और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अधिक मतदान की उम्मीद की थी, लेकिन राज्य टेलीविजन फुटेज में मतदान केंद्रों पर केवल मामूली कतारें दिखाई गईं।
- ऑनलाइन वीडियो में तेहरान में खाली मतदान केंद्र और कम यातायात दिखाया गया, साथ ही उल्लेखनीय सुरक्षा उपस्थिति भी दिखाई दी।
- ये चुनाव बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच हुए।
- अप्रैल में, ईरान ने गाजा में चल रहे आक्रमण के जवाब में इजरायल पर सीधा हमला किया।
- इसके बाद, लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हौथिस जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा हमलों में वृद्धि हुई, जिन्हें ईरान द्वारा समर्थन प्राप्त है।
- जबकि अयातुल्ला खामेनेई राज्य के मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, यह अनिश्चित है कि क्या हालिया घटनाएँ ईरान की विदेश नीति में बदलाव लाएँगी।

Result Mitra

चुनाव नतीजे

- 69 वर्षीय हृदय शल्य चिकित्सक डॉ. मसूद पेजेशकियन ने दूसरे दौर के चुनावों में अति रूढ़िवादी सईद जलीली को हराकर बहुमत हासिल किया।
- उन्हें लगभग 16 मिलियन वोट मिले, जो कुल 30 मिलियन वोटों का 54 प्रतिशत था।
- उनकी जीत का श्रेय देश के प्राथमिक सुधारवादी गठबंधन के समर्थन और सरकार में चल रहे कट्टरपंथी वर्चस्व की संभावना से चिंतित कई ईरानियों के समर्थन को दिया गया।

मसूद पेजेशकियन का नजरिया

- चुनाव प्रचार के दौरान पेजेशकियन ने " ईरान को अलगाव से बाहर निकालने" के लिए पश्चिमी देशों के साथ "रचनात्मक संबंधों" का आह्वान किया।
- उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य शक्तियों के साथ 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का वचन दिया, जिसके तहत प्रतिबंधों में राहत के बदले में ईरान की परमाणु गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- 2018 में वाशिंगटन द्वारा इससे अलग होने के बाद यह समझौता टूट गया।
- ईरान के भीतर, उन्होंने लंबे समय से चले आ रहे इंटरनेट प्रतिबंधों को कम करने और महिलाओं पर अनिवार्य हेडस्कार्फ़ लागू करने वाले पुलिस गश्ती दल का "पूरी तरह" खत्म करने का वादा किया, जो 2022 में पुलिस हिरासत में महसा अमिनी की मौत के बाद से एक हाई-प्रोफाइल मुद्दा है।
- गौरतलब है कि 22 वर्षीय ईरानी महिला को ड्रेस कोड के कथित उल्लंघन के लिए हिरासत में लिया गया था, और उसकी मौत ने देश भर में महीनों तक घातक अशांति फैलाई।
- जबकि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ईरानियों से आग्रह किया कि वे "आगे आने वाले कठिन रास्ते" पर उनके साथ रहें।
- "ईरान के प्रिय लोगों, चुनाव खत्म हो चुका है, और यह हमारे साथ मिलकर काम करने की शुरुआत है। आगे एक कठिन रास्ता है। यह आपके सहयोग, सहानुभूति और विश्वास से ही आसान हो सकता है,"
- "मैं अपना हाथ आपके सामने बढ़ाता हूँ और अपने सम्मान की शपथ लेता हूँ कि मैं आपको इस रास्ते पर नहीं छोड़ूँगा। मुझे मत छोड़िए।"
- अपितु पेजेशकियन ने ईरान के शिया धर्मतंत्र में कोई क्रांतिकारी बदलाव की पेशकश नहीं की है।
- हालांकि, उनके शासन में देश के अनिवार्य हिजाब कानून में ढील देखने को मिल सकती है।
- पेजेशकियन ने अपनी सरकार में अधिक महिलाओं और कुर्द तथा बलूचियों जैसे जातीय अल्पसंख्यकों को शामिल करने का भी वादा किया।
- उन्होंने मुद्रास्फीति को कम करने का भी वादा किया है, जो अब लगभग 40 प्रतिशत पर मँडरा रही है।
- जलीली के साथ एक बहस में, पेजेशकियन ने अनुमान लगाया कि ईरान को 200 बिलियन डॉलर के विदेशी निवेश की आवश्यकता है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह केवल दुनिया भर में संबंधों को सुधारने से ही प्रदान किया जा सकता है।

ईरान में राष्ट्रपति की शक्ति

- कई अन्य देशों के विपरीत, ईरान के राष्ट्रपति के पास राज्य प्रमुख का पद नहीं है।
- ईरानी सरकार की संरचना में सर्वोच्च नेता सर्वोच्च अधिकार रखता है।
- उसके बाद राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद, संरक्षक परिषद और शस्त्र बल हैं।
- 1989 से सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

Result Mitra

- वह राज्य के प्रमुख और कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य करते हैं, जिनके पास राष्ट्रीय पुलिस और नैतिकता पुलिस को कमांड करने की शक्ति है।
- इसके अतिरिक्त, वह इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कोर की देखरेख करते हैं और न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं।
- राष्ट्रपति, दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, ईरान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
- राष्ट्रपति के रूप में पेजेशकियन का दूसरा सबसे बड़ा पद होगा और वह घरेलू और विदेश नीति दोनों पर प्रभाव डालेंगे।
- उनके पास आर्थिक नीति निर्धारित करने का अधिकार भी होगा, लेकिन पुलिस पर उनकी शक्ति सीमित होगी,
- पेजेशकियन का मुख्य कार्य खामेनेई द्वारा उल्लिखित राज्य नीतियों को लागू करना होगा।

ईरानी जनता की अपेक्षाएं

- ईरानियों में पेजेशकियन की जीत के प्रति मिश्रित भावनाएं हैं, कुछ लोग प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, जबकि अन्य संशय में हैं।
- राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार मज़ियार खोसरावी के अनुसार नए राष्ट्रपति ने ईरान में "समस्याओं के तत्काल समाधान का वादा नहीं किया",
- "लोगों ने उन्हें इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका दृष्टिकोण दुनिया के साथ-साथ चलने का था, जो वर्तमान सरकार से पूरी तरह अलग था।"
- हालांकि लोगों को उम्मीद है कि वह कुछ अच्छे बदलाव ला सकेंगे और देश के कुछ मुद्दों को सुलझा सकेंगे, विशेषकर अर्थव्यवस्था के मामले में।

नए राष्ट्रपति के समक्ष भावी चुनौतियां

- पेजेशकियन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि राज्य संस्थाओं पर अभी भी रूढ़िवादी लोगों का वर्चस्व है।
- ऐसी ही एक संस्था ईरानी संसद (मजलिस) है, जिसका चुनाव मार्च में हुआ था और इसमें रूढ़िवादी और अति रूढ़िवादी लोगों का प्रभुत्व है।
- अपितु अधिकांश रूढ़िवादी नेताओं का मानना है कि हिजाब या किसी अन्य वैचारिक मामले से निपटना राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। उनके अनुसार यह एक धार्मिक मामला है।
- पेजेशकियन को "घरेलू स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों तथा विदेश में कूटनीतिक भागीदारी" को सुरक्षित रखने के लिए कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा।
- इसके अलावा अमेरिका और यूरोप के साथ 2015 के समझौते को पुनर्जीवित करने के कूटनीतिक प्रयास पिछले कुछ वर्षों में विफल रहे हैं।
- साथ ही ईरान का राष्ट्रपति चुनाव इजरायल और तेहरान के सहयोगी हमास के बीच गाजा युद्ध को लेकर बढ़े क्षेत्रीय तनाव के बीच हुआ है, जिसमें सीरिया, लेबनान, इराक और यमन के अन्य ईरान समर्थित आतंकवादी समूह भी शामिल हो गए हैं।

भारत-ईरान संबंध

- भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिसमें व्यापार मार्ग फारस की खाड़ी और अरब सागर के माध्यम से दक्षिणी ईरान और भारत के तट को जोड़ते थे।

Result Mitra

- भारत और ईरान ने 15 मार्च 1950 को एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, और तेहरान घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें "समान, बहुलवादी और सहकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था" के लिए एक साझा दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया।
- ईरान की अनूठी भौगोलिक स्थिति भारत को मध्य एशिया, अफगानिस्तान और यूरेशिया के बाजारों तक पहुंच प्रदान करती है।
- गैस भंडार के मामले में ईरान विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो ईंधन विविधीकरण, डीकार्बोनाइजेशन और 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी का अवसर प्रस्तुत करता है।
- भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो 2021 से 48% की वृद्धि को दर्शाता है।
- भारत ईरान को चीनी, मानव निर्मित स्टेपल फाइबर, विद्युत मशीनरी और कृत्रिम आभूषण निर्यात करता है, जबकि सूखे मेवे, रसायन और कांच के बने पदार्थ आयात करता है।
- ईरान ने भारत को उन देशों की सूची में शामिल किया, जिनके नागरिकों को यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।
- भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2013 में हुई थी और 2018 में इसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कर दिया गया और भारत ने हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत फ़ारसी को नौ शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया।

बदलती अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का संबंधों पर प्रभाव

- भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत होने के बावजूद, देश ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया है।
- हालाँकि, अगर पेजेशकियन परमाणु विवाद के संबंध में पश्चिम के साथ बातचीत करने में सफल होते हैं, तो इससे आर्थिक प्रतिबंधों को अंततः हटाया जा सकता है, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा।
- ईरान अपने तेल निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भारत संभावित रूप से कच्चे तेल का एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी आपूर्तिकर्ता प्राप्त कर सकता है।
- पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार में 26% की कमी आई है, जो $1.836 बिलियन है।
- भारत और ईरान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और चाबहार बंदरगाह के विकास जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी सहयोग कर रहे हैं।
- अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद, भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है।
- भारत ने चाबहार में शाहिद-बेहेश्टी बंदरगाह में 120 मिलियन डॉलर का निवेश करने का भी वादा किया है और ईरान में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 250 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा की पेशकश की है।
- INSTC, ईरान के माध्यम से भारत को रूस से जोड़ने वाला 7,200 किलोमीटर लंबा परिवहन गलियारा है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ने और मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारत-ईरान संबंधों की आगे की राह

- भारत के पास ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने में नेतृत्व करने का अवसर है।
- द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, भारत को तरजीही व्यापार समझौतों के माध्यम से ईरानी कृषि वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर विचार करना चाहिए।

Result Mitra

- ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स में निवेश करने के साथ-साथ समुद्री लाइनों को विकसित करके, भारत द्विपक्षीय व्यापार का काफी विस्तार कर सकता है।
- आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।
- रूसी संघ और मध्य एशिया और काकेशस के अन्य देशों के साथ संयुक्त प्रयास भारत और ईरान के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
- ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बना सकता है।